STATESMAN, Delhi, 27.8.2025
Page No. 2, Size:(17.55)cms X (23.22)cms.

NHRC notice to Delhi Chief Secy, Commissioner over Daryaganj building collapse

STATESMAN NEWS SERVICE
New Delhi, 26 August

Taking suo motu cognizance of the reported death of three labourers in a building collapse in Daryaganj, the National Human Rights Commission (NHRC) on Tuesday issued notices to the Delhi chief secretary, commissioner, MCD, and DCP, calling for a detailed report on the matter within 2 weeks. "The National Human Rights Commission (NHRC), India, has taken suo motu cognisance of media reports that three labourers died and several others narrowly escaped when a portion of an under-construction four-story building collapsed in the Daryaganj area of Delhi on August 20. The deceased were migrant workers from Bihar," the rights panel said in a statement. The Commission has examined contents of news report, which, if true, raise serious issues of human rights violations.

Accordingly, it has issued notices to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi; Commissioner, Municipal Corporation; and Deputy Commissioner of Police, Central Delhi, calling for a detailed report on matter within two weeks. According to media report, carried on August 21, around 15 labourers were present at site when incident occurred.

PIONEER (HINDI), Delhi, 27.8.2025
Page No. 3, Size:(16.83)cms X (18.52)cms.

दरियागंज में इमारत गिरने का मामला

एनएचआरसी ने मजदूरों मौत का स्वतः संज्ञान लिया

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के दरियागंज इलाके में एक निमार्णाधीन इमारत गिरने से तीन मजदूरों की मौत की घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। यह घटना 20 अगस्त को हुई थी, जिसमें तीन प्रवासी मजदूरों की जान चली गई थी। ये मजदूर बिहार के रहने वाले थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 20 अगस्त, 2025 को एक चार मंजिला निमार्णाधीन इमारत का एक हिस्सा गिर गया, जिसके मलबे में दबकर तीन मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य बाल-बाल बच गए।

आयोग ने जारी किए नोटिस

एनएचआरसी ने इस घटना को मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए दिल्ली के मुख्य सचिव, नगर निगम आयुक्त और मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। पुलिस ने भी इमारत के मालिक और ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

इस घटना के समय इमारत पर लगभग 15 मजदूर काम कर रहे थे।

PUNJAB KESARI, Delhi, 27.8.2025
Page No. 6, Size:(6.14)cms X (5.11)cms.

दरियागंज में बिल्डिंग गिरने के मामले में मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): गत दिनों दिल्ली के दरियागंज इलाके में एक निर्माणाधीन चार मंजिला इमारत का हिस्सा ढहने से हुई तीन मजदूरों की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के मुख्यसचिव, एमसीडी कमिश्नर व सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी को नोटिस जारी किया है। एनएचआरसी ने इस हादसे से संबंधित मीडिया रिपोर्टों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए पूरे मामले पर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। आयोग ने इस प्रेसनोट जारी कर कहा कि हमने समाचार रिपोर्ट की विषय-वस्तु की जांच की है, यदि यह सच है तो इससे मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठता है। दरअसल, 21 अगस्त को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दरियागंज इलाके में निर्माणाधीन इस चार मंजिला इमारत के ढहने के समय लगभग 15 मजदूर घटनास्थल पर मौजूद थे। हादसे में तीन मजदूरों की मौत हो गई और कई अन्य बाल-बाल बच गए। पुलिस ने इस मामले इमारत के मालिक और ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

मुख्य सचिव, एमसीडी कमिश्नर व डीसीपी को जारी किया नोटिस

Wed, 27 August 2025
https://mpaper.punjabkesari.com/c/78033406

DAINIK JAGRAN, Delhi, 27.8.2025
Page No. 3, Size:(3.74)cms X (5.60)cms.

निर्माणाधीन इमारत गिरने की घटना पर एनएचआरसी ने मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने 20 अगस्त को दिल्ली के दरियागंज क्षेत्र में निर्माणाधीन इमारत गिरने की घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार और अन्य संबंधित एजेंसियों से जवाब मांगा है। आयोग ने मुख्य सचिव, नगर निगम आयुक्त और पुलिस उपायुक्त (मध्य दिल्ली) को नोटिस भेजकर दो सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

इस हादसे में बिहार के तीन प्रवासी श्रमिकों की मृत्यु हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए। घटना के समय लगभग 15 श्रमिक कार्य स्थल पर उपस्थित थे। भवन मालिक और ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आयोग ने इसे गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन मानते हुए अधिकारियों से घटना के कारण, मृतकों के परिवारों को सहायता, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव के उपायों की जानकारी मांगी है।

DAINIK JAGRAN, Bhagalpur, 27.8.2025
Page No. 13, Size:(8.15)cms X (5.34)cms.

लापता चार नाबालिग बच्चियां बंगाल में मिली

दसवीं में पढ़ने वाली चार लड़कियां स्कूल के लिए निकली...दलाल ने मालदा में कर दिया सबका सौदा

संवाद सहयोगी जागरण नवगछिया: परबत्ता थाना क्षेत्र के एक गांव से शनिवार को लापता हुई चार नाबालिग बच्चियों को नवगछिया पुलिस ने कुछ ही घंटों में पश्चिम बंगाल के खालतीपुर स्टेशन से सुरक्षित बरामद कर लिया। सूत्रों के अनुसार, 25 अगस्त 2025 को शाम करीब 5:30 बजे परबत्ता थाना को सूचना मिली कि एक गांव की चार नाबालिग बच्चियां स्कूल जाने के बाद घर नहीं लौटी हैं। पुलिस अधीक्षक नवगछिया के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने जीआरपी नवगछिया और जीआरपी मालदा (पश्चिम बंगाल) के सहयोग से पुलिस टीम ने बच्चियों को खालतीपुर रेलवे स्टेशन से सुरक्षित बरामद किया। फिलहाल सभी बच्चियों को पूछताछ के लिए लाया जा रहा है।

संवाद सूत्र जागरण नवगछिया: नवगछिया में एकसाथ 4 नाबालिग लड़कियों के गायब हो जाने से सनसनी मच गई। ये सभी सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा की छात्रा हैं। जानकारी जुटाने पर पता चला कि किसी युवती के बहकावे में आकर वे सभी घर से बिना बताए बंगाल चली गई हैं। इस बीच दलालों की नजर भी उनपर पड़ गई और लड़कियों के बेचने वाले गिरोह ने इनका सौदा भी तय कर दिया। हालांकि, पुलिस की तत्परता से सभी नाबालिगों को बिकने से बचा लिया गया। मालदा स्टेशन से जीआरपी ने चारों लड़कियों को सुरक्षित बरामद कर लिया है। जिला के परबत्ता थाना क्षेत्र के एक गांव से चार नाबालिग लड़कियां गायब हो गई थीं।

NHRC.IN

एनएचआरसी, भारत ने दिल्ली के दरियागंज इलाके में एक इमारत गिरने की घटना में तीन मजदूरों की कथित मौत का स्वतः संज्ञान लिया है।

प्रेस विज्ञप्ति

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

https://nhrc.nic.in/media/press-release/nhrc-india-takes-suo-motu-cognizance-reported-death-three-labourers-building

नई दिल्ली: 26 अगस्त, 2025

एनएचआरसी, भारत ने दिल्ली के दरियागंज इलाके में एक इमारत गिरने की घटना में तीन मजदूरों की कथित मौत का स्वतः संज्ञान लिया है।

दिल्ली के मुख्य सचिव, एमसीडी आयुक्त और मध्य दिल्ली के डीसीपी को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने मीडिया रिपोर्टों पर स्वतः संज्ञान लिया है कि 20 अगस्त, 2025 को दिल्ली के दरियागंज इलाके में एक निर्माणाधीन चार मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिरने से तीन मजदूरों की मौत हो गई और कई अन्य बाल-बाल बच गए। मृतक बिहार के प्रवासी श्रमिक थे।

आयोग ने समाचार रिपोर्ट की विषयवस्तु की जाँच की है और यदि यह सत्य है, तो मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाती है। तदनुसार, आयोग ने मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, नगर निगम आयुक्त और मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट माँगी है।

21 अगस्त, 2025 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, घटना के समय लगभग 15 मज़दूर घटनास्थल पर मौजूद थे। इमारत के मालिक और ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

*****

PIB

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के दरियागंज इलाके में एक इमारत ढहने की घटना में कथित तौर पर तीन श्रमिकों की मृत्यु के मामले पर स्वतः संज्ञान लिया।

आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली नगर निगम के आयुक्त और मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त को नोटिस जारी करके इस मामले पर दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2160805

Posted On: 26 AUG 2025 12:08PM by PIB Delhi

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मीडिया में आई उन खबरों पर स्वतः संज्ञान लिया है जिनमें बताया गया था कि 20 अगस्त, 2025 को दिल्ली के दरियागंज इलाके में निर्माणाधीन चार मंजिला भवन का एक हिस्सा गिरने से तीन श्रमिकों की मृत्यु हो गई और कई अन्य बाल-बाल बच गए। सभी मृतक बिहार के प्रवासी श्रमिक थे।

आयोग ने समाचार रिपोर्ट की विषय-वस्तु की जांच की है और कहा है कि यदि यह जानकारी सही है तो यह मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। तदनुसार, आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के मुख्य सचिव, दिल्ली नगर निगम के आयुक्त और मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है।

21 अगस्त, 2025 को मीडिया में प्रकाशित समाचारों के अनुसार, उक्त घटना के समय लगभग 15 श्रमिक घटनास्थल पर थे। भवन के मालिक और ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

***

पीके/केसी/केके/एसके

(Release ID: 2160805)

Tribune

Commission seeks report on Daryaganj building collapse

Issues notices to Chief Secy, MC chief

https://www.tribuneindia.com/news/delhi/commission-seeks-report-on-daryaganj-building-collapse/

Tribune News Service

New Delhi, Updated At : 08:53 AM Aug 27, 2025 IST

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of media reports regarding the collapse of an under-construction building in Daryaganj here on August 20, which claimed the lives of three migrant labourers from Bihar and left several others narrowly escaping death.

The commission observed that the contents of the report, if true, raised “serious issues of human rights violations” involving the safety and dignity of workers at construction sites, it said in a press note.

Moreover, the commission has issued notices to the Chief Secretary of the Government of NCT of Delhi, Commissioner of the Municipal Corporation and the Deputy Commissioner of Police, Central Delhi, seeking a detailed report within two weeks.

The incident took place on August 20 when a building being demolished collapsed near Sadbhavna Park in Central Delhi’s Daryaganj, leaving three workers dead.

The deceased were identified as Zubair (24), his uncle Taufiq (32) and Gulsagar (30). As many as 15 persons were working at the site when the incident took place, the police said.

Zubair and Taufiq were on the second floor when a portion of it collapsed. Gulsagar rushed in to save the duo, but he also got trapped underneath the debris as the rest of the portion came down, they said.

The Statesman

NHRC notice to Delhi Chief Secy, Commissioner over Daryaganj building collapse

The Commission has examined the contents of the news report, which, if true, raise serious issues of human rights violations.

https://www.thestatesman.com/cities/nhrc-notice-to-delhi-chief-secy-commissioner-over-daryaganj-building-collapse-1503477071.html

Statesman News Service | New Delhi | August 26, 2025 6:10 pm

Taking suo motu cognizance of the reported death of three labourers in a building collapse in Daryaganj, the National Human Rights Commission (NHRC) on Tuesday issued notices to the Delhi chief secretary, commissioner, MCD, and DCP, calling for a detailed report on the matter within 2 weeks.

“The National Human Rights Commission (NHRC), India, has taken suo motu cognisance of media reports that three labourers died and several others narrowly escaped when a portion of an under-construction four-story building collapsed in the Daryaganj area of Delhi on August 20. The deceased were migrant workers from Bihar,” the rights panel said in a statement.

The Commission has examined the contents of the news report, which, if true, raise serious issues of human rights violations.

Accordingly, it has issued notices to the Chief Secretary, Government of NCT of Delhi; the Commissioner, Municipal Corporation; and the Deputy Commissioner of Police, Central Delhi, calling for a detailed report on the matter within two weeks.

According to the media report, carried on August 21, around 15 labourers were present at the site when the incident occurred. A case has been registered against the owner of the building and the contractor.

The matter came to light when three workers lost their lives after a three-story building collapsed near Sadbhavna Park in Central Delhi’s Daryaganj on Wednesday.

The deceased, who have been identified as Zubair, Gulsagar, and Taufiq, were trapped under the debris, police said.

Deputy Commissioner of Police Nidhin Valsan (Central) said that the three men who died were working on site when the incident happened.

Adding to his statement, “Civic authorities, including DDMA, have been informed, and rescue efforts are underway. Legal action will be taken after verification of facts.”

First India

NHRC seeks report on Daryaganj Building Collapse that claimed three lives

https://firstindia.co.in/news/delhi/nhrc-seeks-report-on-daryaganj-building-collapse-that-claimed-three-lives

26 Aug-2025 14:43 PM | By: FirstIndia

New Delhi: The National Human Rights Commission (NHRC) of India has taken suo motu cognisance of media reports concerning the death of three labourers in a building collapse in Delhi's Daryaganj area on August 20, 2025.

The incident occurred when a portion of a four-storey structure, still under construction, suddenly gave way, burying several workers under the debris. The collapse has raised urgent questions about the safety standards and oversight mechanisms in place at construction sites across the city.

At the time of the incident, approximately 15 workers were reportedly present at the site. While most managed to escape with their lives, three individuals--migrant workers from Bihar--were fatally trapped beneath the rubble.

Their deaths have cast a spotlight on the precarious conditions faced by daily-wage labourers, many of whom work without adequate safety gear or structural assurances.

In response to the reports, the NHRC has expressed grave concern over the potential human rights violations involved, particularly in relation to the working conditions and safety protocols for labourers.

The Commission has issued formal notices to the Chief Secretary of Delhi, the Commissioner of the Municipal Corporation, and the Deputy Commissioner of Police for Central Delhi.

These authorities have been directed to submit a comprehensive report within two weeks, detailing the circumstances of the collapse and the measures taken in its aftermath.

Meanwhile, law enforcement agencies have registered a case against the building's owner and the contractor overseeing the reconstruction. The charges include allegations of negligence in construction practices and failure to ensure the safety of workers on site.

Investigations are currently underway, and officials have stated that those responsible will be held accountable.

India Education Diary

NHRC, India takes suo motu cognizance of the reported death of three labourers in a building collapse incident in Daryaganj area of Delhi

https://indiaeducationdiary.in/nhrc-india-takes-suo-motu-cognizance-of-the-reported-death-of-three-labourers-in-a-building-collapse-incident-in-daryaganj-area-of-delhi/

By iednewsdesk | August 26, 2025

The National Human Rights Commission (NHRC), India, has taken suo motu cognizance of media reports that three labourers died and several others narrowly escaped when a portion of an under construction four-storey building collapsed in the Daryaganj area of Delhi on 20th August, 2025. The deceased were migrant workers from Bihar.

The Commission has examined the contents of the news report, if true, raise serious issues of human rights violations. Accordingly, it has issued notices to the Chief Secretary, Government of NCT of Delhi; Commissioner, Municipal Corporation and Deputy Commissioner of Police, Central Delhi, calling for a detailed report on the matter within two weeks.

According to the media report, carried on 21st August, 2025, around 15 labourers were present at the site when the incident occurred. A case has been registered against the owner of the building and the contractor.

The Hans India

NHRC takes suo motu cognisance of death of 3 labourers in Delhi building collapse incident

https://www.thehansindia.com/news/national/nhrc-takes-suo-motu-cognisance-of-death-of-3-labourers-in-delhi-building-collapse-incident-1000661

IANS | 26 Aug 2025 1:26 PM IST

HIGHLIGHTS The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of media reports that three labourers died and several others narrowly escaped when part of an under-construction four-storey building collapsed last week in central Delhi's Daryaganj.

New Delhi: The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of media reports that three labourers died and several others narrowly escaped when part of an under-construction four-storey building collapsed last week in central Delhi's Daryaganj. Taking note of press reports, the apex human rights body said the contents, if true, raise serious concerns of human rights violations.

The NHRC issued notices to the Chief Secretary; Commissioner, Municipal Corporation of Delhi (MCD); and Deputy Commissioner of Police, Central Delhi, and called for a detailed report on the matter within two weeks. According to media reports, the incident occurred on August 20, with around 15 labourers present at the site. The preliminary probe indicated that the incident occurred while the building was being demolished.

The injured were taken to Lok Nayak Jai Prakash Narayan Hospital (LNJP), where they were declared dead. The deceased were identified as Zubair, Gulsagar, and Taufiq, who were working at the site when the structure suddenly gave way. The deceased were migrant workers from Bihar. Soon after the incident, NDRF teams joined the rescue operation, assisting the police, fire brigade, and DDMA personnel. A case was registered against the building owner and the contractor.

Established under the Protection of Human Rights Act, 1993, the NHRC, an autonomous statutory body, is an embodiment of India's concern for the promotion and protection of human rights. Its primary role is to protect and promote human rights, defined as the rights relating to life, liberty, equality, and dignity of individuals guaranteed by the Constitution or embodied in the International Covenants and enforceable by courts in India.

The apex human rights body has the power to take suo motu (on its own motion) action based on media reports, public knowledge or other sources, without receiving a formal complaint of human rights violations.

Devdiscourse

NHRC Intervenes After Tragic Building Collapse in Delhi

The NHRC of India is investigating the collapse of a building in Delhi's Daryaganj area that claimed the lives of three laborers. The incident highlights inadequate safety measures for workers. Authorities have been asked to submit reports, and charges of negligence have been filed against responsible parties.

https://www.devdiscourse.com/article/headlines/3604088-andhra-pradesh-government-extends-suspension-of-senior-ips-officer

Devdiscourse News Desk | Updated: 26-08-2025 13:21 IST | Created: 26-08-2025 13:21 IST

The National Human Rights Commission (NHRC) of India has initiated an investigation following media reports on a tragic building collapse that killed three laborers in Delhi's Daryaganj area on August 20, 2025.

The incident occurred when part of a four-story building under construction collapsed, trapping workers beneath the debris. Approximately 15 workers were on-site, and three migrant laborers from Bihar lost their lives.

This tragedy raises critical questions about safety standards in Delhi construction sites. The NHRC demands reports within two weeks from local authorities and charges have been filed against the building owner and contractor for negligence.

(With inputs from agencies.)

ETV Bharat

दरियागंज हादसे पर NHRC ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब, इमारत का हिस्सा गिरने से तीन मजदूरों की हुई थी मौत - DARYAGANJ BUILIDING COLLAPSE

NHRC ने दिल्ली के मुख्य सचिव, नगर निगम आयुक्त, डीसीपी सेंट्रल दिल्ली को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट तलब की है.

https://www.etvbharat.com/hi/!state/nhrc-took-cognizance-of-the-death-of-three-workers-in-daryaganj-sought-a-report-from-the-delhi-government-delhi-news-dls25082604058

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 26, 2025 at 5:25 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में बीते 20 अगस्त को हुए दर्दनाक हादसा के बाद अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने इस पर संज्ञान लिया है. हादसे में इमारत का एक हिस्सा गिरने से तीन मजदूरों की मौत हो गई थी. ये सभी मजदूर बिहार के मधेपुरा जिले के रहने वाले थे. एनएचआरसी ने मीडिया रिपोर्ट्स का संज्ञान लेते हुए दिल्ली के मुख्य सचिव, नगर निगम आयुक्त व सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

मानवाधिकार आयोग का संज्ञान

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मामला गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन का संकेत देता है. आयोग ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, नगर निगम आयुक्त व सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है. आयोग ने साफ किया है कि मजदूरों की सुरक्षा व उनके अधिकारों की अनदेखी पर जवाबदेही तय की जानी जरूरी है.

बता दें कि दरियागंज स्थित सद्भावना पार्क से सटी करीब 68 साल पुरानी चार मंजिला इमारत को तोड़ने का काम 17 जुलाई से चल रहा था. 20 अगस्त की दोपहर 12 बजे अचानक दीवार गिर गई, जिससे वहां काम कर रहे तीन मजदूर—जुबैर, गुलसागर व तौफीक मलबे में दब गए. मौके पर मौजूद साथी मजदूरों ने उन्हें बाहर निकाला और खून से लथपथ हालत में कंधों पर उठाकर बाहर पहुंचे और लोकनायक अस्पताल ले गए, जहां पर चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया था.

मौके पर कोई मदद को नहीं आया

मृत मजदूरों के साथी मजदूरों मोहम्मद तुरफान व इकबाल ने बताया कि वे सभी मजदूर ठेकेदार के बुलाने पर मधेपुरा, बिहार से आए थे और 700 रुपये की दिहाड़ी पर यहां मकान तोड़ने का काम कर रहे थे. हादसे के समय ठेकेदार मौके पर नहीं था. मजदूरों ने आरोप लगाया था कि न तो मौके पर कोई मदद को आया और न ही एंबुलेंस समय पर पहुंची थी. मृतक मजदूरों के छोटे-छोटे बच्चे हैं. परिजन बेहद गरीब हैं. मजदूरों ने मकान मालिक और ठेकेदार से मृतकों के परिवार वालों को मुआवजा दिलाने की मांग की थी.

दरियागंज में करीब 68 साल पुरानी तीन मंजिला इमारत को तोड़ने का काम पिछले एक माह से चल रहा था. यहां काम करने वाले मोहम्मद तुरफान ने बताया कि यहां पर कुल 15 लोग काम कर रहे थे. सभी कर्मचारी एक ठेकेदार के बुलाने पर आये थे. ये बिहार के मधेपुरा स्थित गणेशपुरी के रहने वाले हैं. सभी कर्मचारी जिस इमारत को तोड़ रहे थे. उसी इमारत में एक कमरे में रह रहे थे.

Insamachar

NHRC ने दिल्ली के दरियागंज इलाके में एक इमारत ढहने की घटना में कथित तौर पर तीन श्रमिकों की मृत्यु के मामले पर स्वतः संज्ञान लिया

https://insamachar.com/nhrc-takes-suo-motu-cognizance-of-the-alleged-death-of-three-workers-in-a-building-collapse-incident-in-delhis-daryaganj-area/

Editor Posted on 26 अगस्त 2025

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मीडिया में आई उन खबरों पर स्वतः संज्ञान लिया है जिनमें बताया गया था कि 20 अगस्त, 2025 को दिल्ली के दरियागंज इलाके में निर्माणाधीन चार मंजिला भवन का एक हिस्सा गिरने से तीन श्रमिकों की मृत्यु हो गई और कई अन्य बाल-बाल बच गए। सभी मृतक बिहार के प्रवासी श्रमिक थे।

आयोग ने समाचार रिपोर्ट की विषय-वस्तु की जांच की है और कहा है कि यदि यह जानकारी सही है तो यह मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। तदनुसार, आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के मुख्य सचिव, दिल्ली नगर निगम के आयुक्त और मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है।

21 अगस्त, 2025 को मीडिया में प्रकाशित समाचारों के अनुसार, उक्त घटना के समय लगभग 15 श्रमिक घटनास्थल पर थे। भवन के मालिक और ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

Janta Se Rishta

NHRC ने दरियागंज इमारत हादसे पर रिपोर्ट तलब की, तीन की मौत

https://jantaserishta.com/delhi-ncr/nhrc-summons-report-on-daryaganj-building-accident-three-dead-4232492

Gulabi Jagat 26 Aug 2025 4:47 PM

New Delhi, नई दिल्ली : भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने 20 अगस्त, 2025 को दिल्ली के दरियागंज इलाके में एक इमारत गिरने से तीन मजदूरों की मौत से संबंधित मीडिया रिपोर्टों पर स्वतः संज्ञान लिया है।यह हादसा उस समय हुआ जब निर्माणाधीन चार मंजिला इमारत का एक हिस्सा अचानक ढह गया, जिससे कई मज़दूर मलबे के नीचे दब गए। इस हादसे ने शहर भर के निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के समय, लगभग 15 मज़दूर घटनास्थल पर मौजूद थे। ज़्यादातर लोग अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रहे, लेकिन तीन लोग, जो बिहार के प्रवासी मज़दूर थे, मलबे में बुरी तरह दब गए।

उनकी मौतों ने दैनिक वेतन भोगी मजदूरों के सामने आने वाली खतरनाक परिस्थितियों पर प्रकाश डाला है, जिनमें से कई पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों या संरचनात्मक आश्वासनों के बिना काम करते हैं।रिपोर्टों के जवाब में, एनएचआरसी ने संभावित मानवाधिकार उल्लंघनों, विशेष रूप से श्रमिकों के लिए कार्य स्थितियों और सुरक्षा प्रोटोकॉल के संबंध में, गंभीर चिंता व्यक्त की है।आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव, नगर निगम आयुक्त और मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त को औपचारिक नोटिस जारी किया है ।

इन प्राधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें इमारत ढहने की परिस्थितियों और उसके बाद उठाए गए कदमों का विवरण दिया जाएगा। इस बीच, कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने इमारत के मालिक और पुनर्निर्माण की देखरेख कर रहे ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इन आरोपों में निर्माण कार्यों में लापरवाही और साइट पर काम करने वाले मज़दूरों की सुरक्षा सुनिश्चित न करने का आरोप शामिल है। जाँच अभी चल रही है और अधिकारियों ने कहा है कि ज़िम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।

Deshbandhu

दरियागंज इलाके में इमारत ढहने की घटना में श्रमिकों की मृत्यु के मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली सरकार से मांगी रिपोर्ट

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में एक इमारत ढहने की घटना में कथित तौर पर तीन श्रमिकों की मृत्यु के मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में दिल्ली के मुख्य सचिव, नगर निगम के आयुक्त और पुलिस उपायुक्त से दो सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है

https://www.deshbandhu.co.in/delhi/national-human-rights-commission-sought-a-report-from-delhi-government-on-the-matter-of-death-of-workers-in-the-building-collapse-incident-in-daryaganj-area-266026

By - एजेंसी 26 Aug 2025 3:03 P

मानवाधिकार आयोग ने श्रमिकों की मृत्यु के मामले में दिल्ली सरकार से मांगा जवाब नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में एक इमारत ढहने की घटना में कथित तौर पर तीन श्रमिकों की मृत्यु के मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में दिल्ली के मुख्य सचिव, नगर निगम के आयुक्त और पुलिस उपायुक्त से दो सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने खबरों पर स्वतः संज्ञान लिया है जिनमें बताया गया था कि 20 अगस्त को यहां दरियागंज इलाके में निर्माणाधीन चार मंजिला भवन का एक हिस्सा गिरने से तीन श्रमिकों की मृत्यु हो गई और कई अन्य बाल-बाल बच गए। सभी मृतक बिहार के प्रवासी श्रमिक थे।

खबरों के अनुसार अनुसार इस दुर्घटना के समय लगभग 15 श्रमिक घटनास्थल पर मौजूद थे। भवन के मालिक और ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आयोग ने कहा है कि यदि जानकारी सही है तो यह मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। आयोग ने इस मामले में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, दिल्ली नगर निगम के आयुक्त और मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है।

Janta Se Rishta

आयोग ने दरियागंज इमारत ढहने पर रिपोर्ट मांगी

https://jantaserishta.com/delhi-ncr/commission-seeks-report-on-daryaganj-building-collapse-4233265

Kiran27 Aug 2025 8:03 AM

Delhi दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने 20 अगस्त को दरियागंज में एक निर्माणाधीन इमारत के ढहने से संबंधित मीडिया रिपोर्टों पर स्वतः संज्ञान लिया है। इस इमारत में बिहार के तीन प्रवासी मज़दूरों की मौत हो गई थी और कई अन्य बाल-बाल बच गए थे।

आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि यदि रिपोर्ट की सामग्री सही है, तो यह निर्माण स्थलों पर मज़दूरों की सुरक्षा और सम्मान से जुड़े "मानवाधिकारों के उल्लंघन के गंभीर मुद्दे" को उठाती है। इसके अलावा, आयोग ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, नगर निगम आयुक्त और मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

यह घटना 20 अगस्त को हुई जब मध्य दिल्ली के दरियागंज में सद्भावना पार्क के पास एक इमारत ढहने से तीन मज़दूरों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान ज़ुबैर (24), उसके चाचा तौफीक (32) और गुलसागर (30) के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि घटना के समय घटनास्थल पर 15 लोग काम कर रहे थे।

fundsforNGOs

Apply for NHRC's Short Film Competition (India)

https://fundsforindividuals.fundsforngos.org/event/apply-for-nhrcs-short-film-competition-india/

Deadline: 31 August 2025

The National Human Rights Commission invites short films for its 'Short Film Competition-2025', which aims at recognizing the creative efforts towards promotion and protection of human rights.

Theme

Human Rights Issues

The themes of short films should be broadly based on various socio-economic, cultural and political rights.

The film could be a documentary, dramatization of real stories or a work of fiction, in any technical format, including animation, within the ambit of right to life, liberty, equality and dignity and covering issues specific to bonded and child labour, women & children's rights, rights in challenges of elderly persons, rights of persons with disability, manual scavenging, right to healthcare, issues of fundamental freedoms, human trafficking, domestic violence, human rights violation due to police atrocities, custodial violence and torture, socio-economic disparities, rights of Nomadic and Denotified Tribes, prison reforms, right to education, right to clean environment including environmental hazards impacting life on planet earth, right to work, right to equality before law, right to food and nutritional security, rights of LGBTQI+, human rights violations due to displacement on account of either man-made or natural calamity, celebrating human rights and values in Indian diversity, development initiatives improving life and living standards, etc.

Funding Information

The prize money for the first, second and third best film will be Rs. 2 lakh, Rs. 1 lakh 50 thousand and Rs. 1 lakh respectively.

The Commission, in addition to three cash awards, certificates and trophies, may also consider giving a "Certificate of Special Mention" along with a cash prize of Rs. 50 thousand each to a maximum of four films, if so recommended by the jury.

Eligibility Criteria

Any Indian citizen can send his/her entry. There is no bar on the number of films sent by an individual for competing in the NHRC's Short Film Award Scheme.

However, each application should have one film only, and films sent once for the NHRC's competition may not compete again under this scheme of the Commission.

The film(s) being sent for this competition should not be on social media platform(s).

The applicant should attach either Aadhar Card / Voter Identity Card / PAN Card / Driving License or any other valid proof of identity issued by a Government authority.

Application Requirements

Language of the film: Any Indian language with sub-titles in English or in English.

Duration of the film: Duration of the short film should not be less than 3 minutes or more than 10 minutes.

Film format: Short films may be in any form (fiction, documentary animation etc.) shot with any device or camera set-up (in MP4 format, Full HD (1080p) or (1920X1820p). Preferably, the size of the short film being sent for the competition should not be more than 2 GB.

Title & Credits: Each film should depict its title and credits, including the names of the producer, writer and director.

Assam Times

PUCL Tribunal Report on Manipur Draws Support and Criticism

https://www.assamtimes.org/node/23513

By SN Sangma | Tuesday, Aug 26, 2025 (05:08 pm)

Shillong, Aug 26, 2025 — The People's Union for Civil Liberties (PUCL)'s Independent People's Tribunal on Manipur, released on August 20, has drawn mixed reactions from civil society, media, and rights groups.

The Tribunal, chaired by former Supreme Court judge Justice Kurian Joseph, is the most extensive civil society effort so far to document the ethnic conflict that began in May 2023. It highlights mass killings, sexual violence, desecration of churches, forced displacements, and the looting of 4,000–7,000 weapons from state armouries. The report accuses the Manipur government of enabling militias such as Arambai Tenggol and Meitei Leepun, while also criticising the silence of the Prime Minister, inaction of the NHRC, and lapses in the judiciary.

Local publications including The Frontier Manipur and Imphal Review of Arts & Politics criticised the report, arguing that it failed to present a "balanced" account by not giving equal space to Kuki-Zo militant activities.

In contrast, rights advocates and groups such as Global Citizens for Kuki-Zo defended the Tribunal's approach, stating that its mandate was to assess state accountability and grave human rights violations, not to provide an ethnographic balance sheet. "Justice is not arithmetic," the group said, warning that calls for symmetry risk denying the scale of atrocities documented.

The report has also been noted for its strong focus on sexual violence, which it describes as evidence of crimes against humanity. While some critics argued that the emphasis was "disproportionate," women's rights organisations welcomed the focus, insisting that such violations cannot be equated with other forms of loss.

The Tribunal further criticised sections of Manipur's media for allegedly acting as "valley echo chambers," suppressing minority voices and reinforcing majoritarian narratives.

As the debate continues, the PUCL report has reopened questions of accountability in Manipur's conflict, with rights groups calling it a landmark step in documenting atrocities, and critics warning against what they see as partial representation.

Janta Se Rishta

उग्रवाद काल में हुई हत्याओं के लिए पुलिस को जेल की सज़ा, Bandi Singh परिवार बरी

https://jantaserishta.com/local/punjab/police-sentenced-to-jail-for-murders-committed-during-insurgency-period-bandi-singh-family-acquitted-4232303

Payal 26 Aug 2025 3:38 PM

Punjab.पंजाब: पंजाब में दशकों से चली आ रही उग्रवाद-कालीन हिंसा की घटनाओं में एक नाटकीय मोड़ आया है। उग्रवाद के वर्षों (1980-1996) के दौरान कथित फर्जी मुठभेड़ों में भूमिका के लिए बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों को दोषी ठहराया गया है। साथ ही, आतंकवाद से जुड़े मामलों में जेल में बंद दर्जनों सिख कैदियों, जिन्हें बंदी सिंह के नाम से जाना जाता है, को रिहा किया गया है। आंकड़ों के अनुसार, मोहाली की एक विशेष सीबीआई अदालत ने पिछले दो वर्षों में कांस्टेबलों से लेकर उप महानिरीक्षकों (डीआईजी) तक 129 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया है। अन्य 60 अधिकारियों पर अभी भी मुकदमा चल रहा है। दोषी ठहराए गए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों में डीआईजी बलकार सिंह सिद्धू, दिलबाग सिंह, कुलतार सिंह और बसरा के साथ-साथ एसएसपी भूपिंदर सिंह, अमरजीत सिंह और सुरिंदर पाल सिंह शामिल हैं।

इन दोषसिद्धियों के समानांतर, 2014-15 में रिहाई के लिए पहचाने गए 96 बंदी सिंहों में से 82 को पिछले पाँच वर्षों में रिहा कर दिया गया। शेष 14 दोषियों में 1995 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के सात दोषी शामिल हैं, जिनमें बलवंत सिंह राजोआना और जगतार सिंह हवारा शामिल हैं। एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव के तहत, भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू (बेअंत सिंह के पोते) ने अपने पहले के रुख को बदलते हुए घोषणा की कि वह और उनका परिवार इन कैदियों की रिहाई का विरोध नहीं करेंगे। पंजाब पुलिस कल्याण संघ ने इन दोषियों की सजा पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि हिंसा के दौर में अधिकारियों ने केवल आदेशों का पालन किया। संघ ने शुक्रवार को राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की और दोषी अधिकारियों की पेंशन बहाली सहित राहत की मांग की। कटारिया ने मुख्य सचिव केएपी सिन्हा और डीजीपी गौरव यादव से मामले की जाँच करने को कहा है।

दूसरी ओर, मानवाधिकार अधिवक्ता कथित न्यायेतर हत्याओं को उजागर करने के लिए दशकों से चल रहे संघर्ष को उजागर करते हैं। कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा और राम कुमार नारायण ने शुरुआत में अमृतसर, तरनतारन और पट्टी में बड़े पैमाने पर फर्जी मुठभेड़ों और लावारिस शवों के अंतिम संस्कार का पर्दाफाश किया था। खालरा के लापता होने के बाद, तत्कालीन एसजीपीसी अध्यक्ष गुरचरण सिंह तोहरा ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसने सीबीआई को जाँच का जिम्मा सौंपा। एजेंसी ने 2001 में 2,087 मामलों की पहचान की और 70 प्राथमिकी दर्ज कीं, जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पीड़ितों को मुआवज़ा दिलाने के रास्ते तलाशे। हालाँकि, सरकारी मंज़ूरी न मिलने के कारण मुकदमों में कई साल की देरी हुई, जब तक कि 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप नहीं किया। तब से, 70 में से 64 प्राथमिकियों पर फ़ैसला सुनाया जा चुका है, और केवल एक को बरी किया गया है। कई मामलों में फोरेंसिक विसंगतियाँ महत्वपूर्ण साबित हुईं—जैसे कई मुठभेड़ों में एक जैसे हथियारों का ज़िक्र, कारतूसों के खोल का मेल न होना और कथित तौर पर आधी रात को हुई गोलीबारी में पीड़ितों के सिर में गोली लगना।

मानवाधिकार वकील नवकिरण सिंह, जो लॉयर्स फॉर ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल के महासचिव हैं, ने कहा, "पंजाब के कुछ पुलिस अधिकारियों की सज़ा सरकारी तंत्र द्वारा किए जा रहे गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों की एक झलक मात्र है... क़ानून का शासन सबसे ऊपर है। अगर क़ानून का शासन नहीं होगा, तो यह समाज में हिंसा को और बढ़ावा देगा।"

New Indian Express

The Salwa Judum judgment and why Justice B Sudershan Reddy is no Naxal sympathiser

If one goes by what the Home Minister Amit Shah said, it can be argued that the entire Supreme Court from 2007 to 2025 has been backing the Maoists.

https://www.newindianexpress.com/web-only/2025/Aug/26/the-salwa-judum-judgment-and-why-justice-b-sudershan-reddy-is-no-naxal-sympathiser

K Ramachandra Murthy | Updated on: 26 Aug 2025, 7:47 pm

4 min read

Is Justice B Sudershan Reddy the right pick for the post of Vice-President?

Amit Shah certainly doesn't believe so. The Union Home Minister asserted that the India Bloc must not have given Justice Reddy the chance to fight the election. He had his reasons.

"Sudershan Reddy is the person who helped Naxalism. He gave the Salwa Judum judgment. If the Salwa Judum judgment had not been given, Naxal terrorism would have ended by 2020," Shah claimed in a speech in Kerala on August 22.

It was a strong statement. But a closer look shows that it doesn't hold up. Justice Reddy has been hailed by his backers as a progressive and democratic jurist, and his Salwa Judum judgment too reflects this.

In fact, if one goes by what the Home Minister said, it can be argued that the entire Supreme Court from 2007 to 2025 has been backing the Maoists.

Twenty-four judges had heard the Salwa Judum matter and issued orders against the Chhattisgarh government. The judges who heard the review petitions all agreed with the essence of Justice Reddy's original judgment. Ergo.

Does this then mean that the Fifth Schedule of the Constitution had been "abrogated" in this case? Does the Constitution and the Supreme Court's responsibility to uphold it no longer exist?

It might just be that the Home Minister has not been properly briefed about the fifth schedule of the Constitution in general and the judgment delivered in the Salwa Judum case in particular. Allow me to explain.

A hearing that began in 2007

The Bench comprising Chief Justice KG Balakrishnan, Justice Tarun Chatterjee and Justice Ravindran was the first to hear the Salwa Judum case in 2007. The following year, the case was heard by the then Chief Justice Balakrishnan and Justice Aftab Alam.

On March 31, 2008, Justice Balakrishnan said state support to Salwa Judum, a civilian militia mobilised to counter Naxalites in Chhattisgarh, would amount to abetting a crime. Justice Aftab Alam agreed that it was a serious matter and a cause of great concern.

On April 15, 2008, the Supreme Court asked the National Human Rights Commission (NHRC) to form an enquiry committee. Then, on December 16, 2008, Chief Justice Balakrishnan and Justice C Sathasivam asked the Central Government to file an Action Taken Report (ATR) on the NHRC report.

This case was heard by the Bench comprising Chief Justice Balakrishnan, Justice P Sathasivam and Justice Chauhan in 2009 followed by the Bench consisting of Chief Justice Balakrishnan, Justice Kapadia and Justice Aftab Alam in 2010.

In March 2010, the Supreme Court asked the petitioners to file a rehabilitation plan and get the consent of the people who will serve on a monitoring committee. By this time, Justice Balakrishnan had retired.

Justice Reddy's judgment and how it has stood the test of time

It was then that Justice B Sudershan Reddy and Justice SH Nijjar started hearing the case in 2011 and the Bench delivered a judgment on July 5 of that year. The judgment said that the state cannot outsource its duties to untrained vigilantes and this violated Article 14 and 21 of the Constitution, including the right to life and equality of the Special Police Officers, as well as the right to life of villagers who are victims of the Salwa Judum.

The Bench also pointed out that it is rapacious state policies that encourage Naxalism. It must be underlined that the Bench did not support Naxalism at any point in time.

In September 2011, the Bench comprising Justice Altamas Kabir, Justice Nijjar and Justice Gyan Sudha Mishra started hearing a revision petition. Justice Kabir confirmed the judgment and acceded to the Centre's petition for revision only to the extent that the judgment would apply solely to Chhattisgarh.

The revision petition was heard by Justice Kabir, Justice Nijjar, Justice Chalameswar and Justice Pinaki Ghose. Justice Gogoi, Justice Kalifulla, Justice Madan Lokur, Justice UU Lalit, Justice MV Ramana, Justice Deepak Gupta, Justice Bobde, Justice Hrishikesh Roy, Justice SVN Batti, Justice BV Nagaratna and Justice Satish Sharma have also heard the matter from 2012 to 2025.

On May 15, 2025, Justice BV Nagaratna and Justice Satish Sharma upheld the order of July 5, 2011, observing it had "crystallised" the prayers in the petition.

They further observed: "We find that having regard to the situation that has emerged over the decades in the state of Chhattisgarh, it is necessary that specific steps are taken so as to bring about peace and rehabilitation of the areas requiring the attention of the State as well as the Central Government who would have to act in a coordinated manner.

"We note that it is the duty of the State of Chhattisgarh as well as the Union of India, having regard to Article 315 of the Constitution, to take adequate steps for bringing about peace and rehabilitation to the residents of the State of Chhattisgarh who have been affected by the violence from whatever quarter it may have arisen."

No ideological sympathy shown towards Naxals

A reading of the directions issued by earlier Supreme Court benches and Justice Reddy's judgments shows that there was no ideological sympathy from the judiciary as a whole, and Justice Reddy individually, towards any ideology other than the principles laid out in the Constitution

Anyone who followed these cases will appreciate the progressive nature of the justices of the Supreme Court. All the 24 judges who heard the case were against the outsourcing of state violence by the Chhattisgarh government. All the judges who heard the revision petition were fully in agreement with the orders passed by Justice Sudershan Reddy and Justice Nijjar some 15 years ago.

It is clear that Justice Sudershan Reddy neither agreed with the philosophy of Naxalites nor endorsed their ways, let alone supporting "Naxal Terrorism". So, stating otherwise will be a travesty.

(Views are personal. The author was editor of several Telugu newspapers including Udayam, Vaartha, Andhra Jyothy and Sakshi.)

Hindustan

सरकार की नीतियों के प्रति लोगों को जागरूक करें: प्रियांक

https://www.livehindustan.com/uttar-pradesh/rampur/story-human-rights-meeting-in-rampur-awareness-and-implementation-of-government-schemes-201756242644806.amp.html

27 अगस्त 2025

Rampur News - रामपुर में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा...

रामपुर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं से संबंधित बैठक हुई। बैठक के दौरान प्रियांक कानूनगो ने कहा कि सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बारे में इस प्रकार से आम जनमानस को जागरूक किया जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित न रहे। उन्होंने मानव अधिकारों का उल्लंघन न हो इसके लिए मजबूत कदम उठाने पर जोर दिया। कानूनगो ने जनपद में संचालित विभिन्न योजनाओं आयुष्मान योजना, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजनों को वितरित किए जाने वाले उपकरण, अनुसूचित जाति की बालिकाओं के साथ होने वाले अपराध के पश्चात मिलने वाली सहायता, प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की स्थिति व मानव अधिकारों के तहत पीड़ितों को मिलने वाले अन्य लाभ संबंधी योजनाओं के बारे में विस्तृत चर्चा की।

उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को समय से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि मानव अधिकार पीड़ितों को समय से न्याय दिलाना सुनिश्चित किया जा सके। सभी अधिकारियों को व्यापक स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी को वृद्धाश्रम में रहने वाले सभी वृद्धजनों के अनिवार्य रूप से आयुष्मान कार्ड बनवाए जाने के निर्देश दिए। जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया कि महिलाओं की समस्याओं को सुनने और उनके निस्तारण के लिए सभी ग्राम सभाओं में वृहद स्तर पर बैठक का आयोजन कराएं। जिसमें महिला सदस्य को अध्यक्ष बनाया जाए जो उनकी समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखे। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को निर्देशित किया कि जनपद में सभी दिव्यांग बच्चों को चिन्हित कर उनकी सूची तैयार करें और ब्लॉक स्तर पर कैंप लगवाकर एक माह के भीतर सभी के प्रमाण पत्र बनवाना सुनिश्चित करें। बैठक में पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संदीप कुमार वर्मा सहित सभी जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

Counter View

Kutch sewer workers' death: Gujarat govt pays Rs 10 lakh compensation. Why not Rs 30 lakh?, asks NHRC

https://www.counterview.net/2025/08/kutch-sewer-workers-death-gujarat-govt.html

Wednesday, August 27, 2025

By A Representative

The National Human Rights Commission (NHRC) had issued a show-cause notice to the Chief Secretary of Gujarat regarding the death of two sanitation workers from asphyxiation three years ago while cleaning a sewer in Mirzapar, Bhuj. Acting on the notice, the state government paid ₹10 lakh each to the families of the deceased workers.

The NHRC, however, has now sought an explanation from the authorities on why the Commission should not direct payment of a higher compensation of ₹30 lakh each to the victim families. The Social Welfare Department's Under Secretary has been asked to submit an action taken report within eight weeks.

The development follows a complaint filed by Ahmedabad-based human rights activist Kantilal U. Parmar, who approached the NHRC citing violation of the workers' right to life under Article 21 of the Constitution.

Parmar said, "This tragic incident reflects a grave violation of human dignity and human rights. The families of the deceased deserve adequate compensation and justice, and strict enforcement of laws is essential to ensure that no more lives are lost in such preventable circumstances."

The case relates to the deaths of two sanitation workers in Bhuj's Mirzapar area in November 2022, when they were called by the local gram panchayat to clean a sewer and suffocated due to toxic gases. A case was initially registered as Accidental Death (No. 49/2022) on November 23, 2022, at A-Division Police Station, Bhuj. Following representations to the District Collector, SP, and DGP, an FIR (No. 1120504221026 dated November 24, 2022) was filed under IPC sections 304, 337, 338, 114, provisions of the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, and Section 9 of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers Act.

Police later arrested the accused linked to the case. Meanwhile, the NHRC has also asked the state to report on measures taken in compliance with its earlier guidelines to prevent sewer-related deaths and to eliminate manual scavenging.

The matter remains under review, with the Commission closely monitoring compliance with its directions.